

निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी और अन्य वगैरह।

बनाम

जितेंद्र भीमराज बीजी और वगैरह

7 अगस्त 1990

[एएम अहमदी एवं एन.एम. कासलीवाल, जे.जे.]

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987: धारा 3(1)-अंतर-गिरोह प्रतिद्वंद्विता का दायरा-गैरकानूनी जमावड़ा-प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के आरोपियों के इरादे को दर्शाने वाला बयान-अंडरवर्ल्ड में वर्चस्व हासिल करने के उद्देश्य से प्रतिद्वंद्वियों की हत्या-अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 3(1) के तहत अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं होता।

धारा 12(1) और 18-नामित न्यायालय-अन्य कानूनों के तहत संबंधित अपराधों की सुनवाई करने और मामलों को नियमित अदालतों में स्थानांतरित करने की शक्ति-धारा 3(i) के तहत आरोप तय करने के लिए नामित न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्टया साक्ष्य का गैर-मौजूदगी-परिणामस्वरूप स्थानांतरण अन्य कानूनों के तहत नियमित अदालतों से जुड़े मामलों को उचित ठहराया गया और धारा 18 के अनुरूप रखा गया।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 227-228। अभियुक्त- उन्मोचित - आरोप बनाये जाने हेतु अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त आधार का निर्धारण। दस्तावेजों एवं अभिलेखों का अवलोकन-ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार का क्षेत्र एवं दायरा।

अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148 और 149 के साथ पठित धारा 302 और 307 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 के तहत आरोप लगाए गए थे। इसके बाद उन पर आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 3 के तहत भी आरोप लगाए गए थे। उन्होंने यह कहते हुए जमानत देने के लिए नामित न्यायालय का रुख किया कि 1987 अधिनियम के प्रावधानों को गलत और दुर्भावनापूर्ण तरीके से लागू किया गया था और नामित न्यायालय ने अधिनियम की धारा 3 को मानना अनुपयुक्त था। महाराष्ट्र राज्य ने नामित न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में अपील दायर की है। चूंकि अभियुक्तों को नियमित अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया गया था, इसलिए उन्होंने सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर के समक्ष जमानत याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद, उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी जमानत याचिकाओं के

लंबित रहने के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 1987 अधिनियम की धारा 3 के तहत नामित न्यायालय में उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। तत्पश्चात्, उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और आरोपियों ने जमानत के लिए फिर से नामित न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नामित न्यायालय ने फिर से माना कि सामग्री समक्ष रखे गए बयान और जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान से अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं हुआ। तदनुसार, इसने आरोपी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227 के तहत आरोपमुक्त कर दिया और मामले को दंड संहिता और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत अन्य अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। नामित न्यायालय के इस आदेश के विरुद्ध, इस न्यायालय में दो अपीलें दायर की गई हैं; एक मृतक के पिता द्वारा और दूसरा राज्य द्वारा। उनके मामले को नियमित अदालत में स्थानांतरित करने के बाद। आरोपी व्यक्तियों ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसे खारिज कर दिया गया। आरोपी व्यक्तियों ने जमानत देने से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इस अदालत में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है।

अपीलों को खारिज करते हुए और याचिका का निपटारा करते हुए,
इस न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित: 1. आरोपी व्यक्तियों द्वारा केवल इस आशय का बयान कि हिंसा का प्रदर्शन लोगों के मन में आतंक या भय पैदा करेगा और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा, अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अपराध नहीं माना जा सकता है। यह वास्तव में हिंसक कृत्य का परिणाम हो सकता है लेकिन इसे अपराध के अपराधियों का इरादा नहीं कहा जा सकता है। [646 एच: 647 ए]

1.1 आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 जैसे आपराधिक कानून को लागू करते समय, अभियोजन पक्ष मामले के रिकॉर्ड और जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजों से यह दिखाने के लिए बाध्य है कि प्रथम दृष्टया उनसे जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वह कानून के अक्षर के अंतर्गत अपराध बनता है। [644 एफ]

1.2 मौजूदा मामले में आरोपी व्यक्तियों के बयान से यह स्पष्ट है कि उनका इरादा प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करना था और इस तरह अंडरवर्ल्ड में प्रभुत्व हासिल करने का उद्देश्य हासिल करना था। ऐसी हिंसा के परिणाम से घबराहट और डर पैदा होना तय है लेकिन अपराध करने का इरादा लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करना नहीं कहा जा सकता है।

इसलिए, नामित न्यायालय का यह मानना पूरी तरह से उचित था कि यह केवल अंतर-गिरोह प्रतिद्वंद्विता का मामला था और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री और जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया था, वे प्रथम दृष्टया अधिनियम के धारा 3 (1) के तहत वर्णित दंडनीय अपराध का खुलासा नहीं करते थे। [647 डी-ई]

2. आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 12(1) नामित न्यायालय को अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के साथ-साथ किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई करने का अधिकार देती है, यदि वह अन्य अपराध इस कानून के अंतर्गत वर्णित अपराध से जुड़ी हुई है। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि तब भी जब नामित न्यायालय निर्णय पर आता है- यह निष्कर्ष निकालते हुए कि अधिनियम की धारा 3(1) के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए कोई पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है, इसलिए आरोपी पर अन्य कानूनों के तहत अपराध करने का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह अधिकार क्षेत्र को हड़पने के समान होगा। इसलिए, धारा 18 में प्रावधान है कि जहां किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद नामित न्यायालय की यह राय होती है कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, तो इसके बावजूद कि उसके पास ऐसे अपराध का

विचारण करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, ऐसे अपराध की सुनवाई के लिए मामले को संहिता के तहत क्षेत्राधिकार वाले किसी भी न्यायालय में स्थानांतरित करेगा। जब नामित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम की धारा 3(1) के तहत आरोप तय करने के लिए कोई प्रथम दृष्टया सबूत नहीं है, तो मामले को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करना उचित था, जिसके पास अकेले ही अधिकार क्षेत्र था। अन्य कानूनों के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए मामले को सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए नामित न्यायालय द्वारा अपनाया गया तरीका स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 18 के अनुरूप है। [647 एफ-एच; 648 ए-सी]

3. कानून के तहत आपराधिक अपराध के लिए कारावास की सजा देने वाले कानूनों को सख्ती से समझा जाना चाहिए। [644 सी]

उस्मानभाई दाऊदभाई मेमन और अन्य, बनाम गुजरात राज्य। [1988] 2 एससीसी 271. संदर्भित।

3.1 जब कोई कानून देश के सामान्य दंड कानूनों के तहत समान अपराधों के लिए निर्धारित दंड की तुलना में विशेष या बड़ी हुई सजा प्रदान करता है, तो न्यायाधीश पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च जिम्मेदारी और कर्तव्य डाला जाता है कि लगाए गए आरोप का समर्थन करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा इसलिए,

जब कोई कानून गंभीर दंडात्मक परिणामों वाले किसी व्यक्ति का सामना करता है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त देखभाल की जानी चाहिए कि जिन लोगों को विधायिका ने कानून की स्पष्ट भाषा से कवर करने का इरादा नहीं किया है, उन्हें कानून की भाषा खींचकर फंसाया नहीं जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिस न्यायिक अधिकारी को यह तय करने के लिए बुलाया जाए कि अधिनियम के तहत आरोप तय करने का मामला बनता है या नहीं, वह नकारात्मक रवैया अपनाए। यदि अभियोजन पक्ष यह दर्शाता है कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री और जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उससे यह संदेह होता है कि आरोपी ने उसके खिलाफ कथित अपराध किया है, तो उसे आरोप तय करना चाहिए।
[644 जी-एच; 645 ए]

4. न्यायालय को इस बात पर विचार करते समय कि क्या आरोपी को बरी किया जाए या उसके खिलाफ आरोप तय किया जाए यानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227-228 के चरण में रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। यह पता लगाने के लिए कि क्या उनके अंकित मूल्य पर सामने आए तथ्य कथित अपराध को बनाने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। चूंकि ट्रायल कोर्ट है तय करने के चरण में कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार

मौजूद हैं या नहीं, इसकी जांच आवश्यक रूप से यह तय करने तक सीमित होनी चाहिए कि क्या रिकॉर्ड और दस्तावेजों से उभरने वाले तथ्य उस अपराध का गठन करते हैं जिसके लिए आरोपी पर आरोप लगाया गया है। उस स्तर पर यह उस सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्यों को छांट सकता है लेकिन अनाज को भूसी से अलग करने की दृष्टि से साक्ष्यों को एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार है और इस सीमित उद्देश्य के लिए उसे रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के साथ-साथ अभियोजन पक्ष द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों पर भी विचार करना चाहिए। 1643 ई; 641 एफ-जी]

बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह, [1978] 1 एससीआर 257; भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल एवं अन्य, [1979] 2 एससीआर 229 एवं अधीक्षक। और कानूनी मामलों के स्मरणकर्ता, पश्चिम बंगाल बनाम अनिल कुमार भुंजा और अन्य, [1979] 4 एससीसी 274, संदर्भित।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील 1989 के क्रमांक 703, 712 और 1990 के 13।

सीआरएल में जलगांव में नामित न्यायालय/न्यायाधीश के निर्णय और आदेश दिनांक 27.10.1989 से। विविध. आवेदन. टी.ए.डी.ए. में 1989

की संख्या 524 सन् 1989 का केस नंबर 9 दिनांक 2.9. 1989 में सीआरएल। विविध. आवेदन. 1989 की संख्या 357.

साथ

विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) क्रमांक 2459, 1989।

सीआरएल में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.11.1989 से। आवेदन. 1989 की संख्या 687.

सीआरएल में अपीलकर्ता-व्यक्तिगत रूप से। 1990 का ए. नं. 703.

बी.ए. मासोदकर, यू.आर. ललित और जी.बी. अपीलार्थी की ओर से साठे याचिकाकर्ता।

वी.एन. पाटिल और ए.एस. उत्तरदाताओं के लिए भस्मे।

एस.के. हस्तक्षेपकर्ता के लिए पास करें।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

अहमदी, न्यायाधिपती - ये तीन अपीलें उपरोक्त विशेष अनुमति के पांच याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पुलिस के नेतृत्व में आरोप स्तर से उत्पन्न हुई हैं। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987, (इसके बाद इसे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 3, आईपीसी की धारा 147, 148 और 149 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302,

307 और बॉम्बे पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 37 के तहत याचिका, आपराधिक अपील संख्या 703/89 के अपीलकर्ता के बेटे राजू उर्फ अवतार सिंह की हत्या के लिए, और उसके साथी केशव विट्ठल, पहले मुखबिर को हुई चोटों के लिए। इन कार्यवाहियों को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

12 जुलाई 1989 की दोपहर करीब तीन बजे जब राजू और उसका साथी केशव मोटर साइकिल से जा रहे थे। उन्हें आरोपी जितेंद्र और पहलवान नामक एक अन्य व्यक्ति ने रोका था। उनके बीच कुछ विवाद और तीखी नोकझोंक के बाद अन्य तीन आरोपी मौके पर पहुंचे। उनमें से दो चाकुओं से लैस थे और तीसरे के पास लोहे की रॉड थी। उन्हें देखकर केशव, जो पीछे की सीट पर था, अपनी एडी पर बैठ गया, जिसके बाद राजू, जो चालक की सीट पर था, मोटरसाइकिल छोड़कर दूसरी दिशा में भाग गया। आरोपियों में से दो व्यक्ति राजू के पीछे भागे, जबकि पहलवान सहित अन्य ने केशव का पीछा किया। ज्यादा बोलने पर आरोपी विजय ने केशव के सीने पर चाकू से वार कर दिया और उसके साथी संतोष ने लोहे की रॉड से वार कर दिया। इसके बाद तीनों घटनास्थल से भाग गए। आरोप है कि राजू का पीछा करने वाले अन्य दो लोगों ने उसकी हत्या कर दी क्योंकि वह सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ा मिला था। दोनों घायलों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल पहुंचते ही राजू ने दम

तोड़ दिया। हालाँकि, केशव पर चिकित्सा उपचार का असर हुआ और वह सबूत देने के लिए बच गया।

उसी दिन शाम करीब साढ़े पांच बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट घायल केशव ने दर्ज करायी थी। इसके आधार पर 1989 की सीआर संख्या 138 में एक प्रविष्टि की गई और धारा 302 और 307 के साथ धारा 147, 148 और 149 आईपीसी और बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 37 के तहत मामला दर्ज किया गया। आरोपियों को 15 जुलाई, 1989 को गिरफ्तार किया गया और 9 दिनों के लिए रिमांड पर लिया गया, जिसकी अवधि 29 जुलाई, 1989 तक बढ़ा दी गई, जिसके आधार पर जांच अधिकारी ने अधिनियम की धारा 3 लागू की। 3 अगस्त, 1989 को अभियुक्त ने अन्य बातों के साथ-साथ जमानत के लिए नामित न्यायालय, जलगांव में एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि अधिनियम के प्रावधानों को गलत और दुर्भावनापूर्ण तरीके से लागू किया गया था। उक्त आवेदन पर 2 सितंबर, 1989 को नामित न्यायालय द्वारा सुनवाई और निर्णय लिया गया, जिसमें यह माना गया कि अधिनियम की धारा 3 को गलत तरीके से लागू किया गया था। उस आदेश के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य ने आपराधिक अपील संख्या 712/89 दायर की गई। चूंकि आरोपियों को नियमित अदालत से संपर्क करने का निर्देश दिया गया था, इसलिए उन्होंने अतिरिक्त सत्र

न्यायाधीश, चतुर्थ, अहमदनगर के समक्ष दो जमानत याचिकाएं दायर कीं। हालाँकि, उक्त जमानत आवेदन 25 सितंबर, 1989 को खारिज कर दिए गए थे। उक्त अस्वीकृति के खिलाफ आरोपी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जबकि वे मामले उच्च न्यायालय में लंबित थे, अभियोजन पक्ष ने जलगांव में नामित न्यायालय में अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इस पर हाईकोर्ट ने आवेदन खारिज कर दिए। आरोपी ने जमानत के लिए फिर से नामित अदालत का दरवाजा खटखटाया। नामित न्यायालय एक बार फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 3 लागू नहीं होता और उस आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227 (इसके बाद इसे ' कोड' कहा जाएगा) के तहत आरोपी को उन्मोचित कर दिया गया। 27 अक्टूबर, 1989 के उक्त आक्षेपित आदेश द्वारा मामले को अन्य आरोपों पर सत्र न्यायालय, अहमदनगर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया था और अभियुक्तों को जमानत के लिए उस अदालत में जाने की स्वतंत्रता दी गई थी। उक्त आदेश के विरुद्ध राजू के पिता द्वारा आपराधिक अपील संख्या 703/89 दायर की गई है, जबकि महाराष्ट्र राज्य ने आपराधिक अपील संख्या 13/90 दायर की है। इसके बाद आरोपियों ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया लेकिन हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी और

मामले की जल्द सुनवाई का निर्देश दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध मूल अभियुक्त द्वारा विशेष अनुमति याचिका क्रमांक 2459/ 89 प्रस्तुत किया गया है।

यह अधिनियम आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों की रोकथाम और उनसे निपटने तथा उनसे जुड़े या उनके आनुषंगिक मामलों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। धारा 2(डी) अभिव्यक्ति 'विघटनकारी गतिविधि' को धारा 4 में दिए गए अर्थ के अनुसार परिभाषित करती है। धारा 2(एच) अभिव्यक्ति 'आतंकवादी कृत्य' को धारा 3(1) के तहत दिए गए अर्थ के अनुसार परिभाषित करती है। अधिनियम धारा 3(1) के प्रासंगिक भाग में प्रावधान है कि जो भी, (i) स्थापित कानून के अनुसार सरकार को भयभीत करने के इरादे से या (ii) लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करने के इरादे से या (iii) किसी भी वर्ग को अलग-थलग करने के इरादे से लोगों के बीच या (iv) लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच सौहार्द को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए, उसमें उल्लिखित घातक हथियारों में से किसी का उपयोग करके कोई कार्य या चीज इस तरह से करता है जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है / या उसे चोट नहीं लगती है या व्यक्ति, आतंकवादी कृत्य करता है। धारा 3(2) ऐसे कृत्य के लिए दंड का प्रावधान करती है। धारा 4(1)

किसी भी विघटनकारी गतिविधि में शामिल होने पर दंड का प्रावधान करती है। धारा 4(2) एक विघटनकारी गतिविधि को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है किसी भी तरीके से की गई कोई भी कार्रवाई (i) जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर सवाल उठाती है, बाधित करती है या बाधित करने का इरादा रखती है, या (ii) जिसका उद्देश्य भारत के किसी भी हिस्से के अधिग्रहण या भारत के किसी भी हिस्से को संघ से अलग करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दावा करना या उसका समर्थन करना है। धारा 6 किसी भी आतंकवादी या विघटनकारी की सहायता के लिए बड़े हुए दंड का प्रावधान करती है। अधिनियम का भाग III प्रयास करने के लिए मशीनरी बनाता है। आतंकवादियों और विघटनवादियों पर अधिनियम के तहत किसी भी अपराध को अंजाम देने का आरोप लगाया गया है। धारा 9 केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, या ऐसे मामले या वर्ग या मामलों के समूह के लिए एक या अधिक नामित न्यायालयों का गठन करने का अधिकार देती है, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है। धारा 9(6) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी निर्दिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश या अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति

से ठीक पहले किसी राज्य में सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न हो। धारा 11 कहती है कि अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध की सुनवाई अधिनियम की धारा 9(1) के तहत गठित एक नामित न्यायालय द्वारा की जाएगी। धारा 12(1) हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है और इस प्रकार है:

"किसी भी अपराध की सुनवाई करते समय, एक नामित न्यायालय किसी अन्य अपराध की भी सुनवाई कर सकता है, जिसके साथ आरोपी पर, संहिता के तहत, उसी मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से जुड़ा हुआ है।"

धारा 14 नामित न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों को निर्धारित करती है। धारा 14 की उपधारा 3 हमारे उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन। नामित न्यायालय के पास किसी भी अपराध के प्रयोजन के लिए सत्र न्यायालय की सभी शक्तियाँ होंगी और वह ऐसे अपराधों की सुनवाई करेगा जैसे कि यह सत्र न्यायालय था जहाँ तक

प्रक्रिया के अनुसार हो सकता है सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे के लिए संहिता में निर्धारित है।"

धारा 16 गवाहों को सुरक्षा प्रदान करती है। धारा 17 नामित न्यायालयों द्वारा मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रिया प्रदान करती है। धारा 18 नामित न्यायालयों को मामलों को नियमित न्यायालयों में स्थानांतरित करने का अधिकार देती है। यह अनुभाग इस प्रकार है:

"जहां, किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद, एक नामित न्यायालय की राय है कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, तो वह, इस बात के बावजूद कि उसके पास ऐसे अपराध का मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, मामले को ऐसे अपराध के मुकदमे के लिए स्थानांतरित कर देगा। संहिता के तहत क्षेत्राधिकार रखने वाली किसी भी अदालत और जिस अदालत में मामला स्थानांतरित किया गया है वह अपराध की सुनवाई इस तरह से आगे बढ़ा सकती है जैसे कि उसने अपराध का संज्ञान लिया हो।"

धारा 19 तथ्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील करने का प्रावधान करती है। निर्दिष्ट न्यायालय के अंतरिम आदेश के अलावा किसी भी निर्णय, वाक्य या आदेश से और कानून पर धारा 20(1) अधिनियम या

नियमों के तहत अपराध को संज्ञेय बनाती है। धारा 20 की उपधारा (8) में कहा गया है कि संहिता में किसी भी बात के बावजूद, अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम के तहत दंडनीय अपराध का आरोपी कोई भी व्यक्ति, यदि हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने बांड पर तब तक रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक सरकारी वकील को उसकी रिहाई का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया है और जहां वह अपनी रिहाई का विरोध करता है, अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। जमानत पर रहते हुए अपराध धारा 21 नामित न्यायालय को यह मानने का आदेश देती है, जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, कि आरोपी ने धारा 3(1) के तहत अपराध किया है, यदि खंड (ए) से (डी) में निर्धारित चार चीजों में से एक साबित हो जाता है। धारा 22 अपराधी की तस्वीर के आधार पर उसकी पहचान करने की अनुमति देती है। धारा 28 केंद्र सरकार को उप-धारा (2) के खंड (ए) से (एफ) में निर्धारित किसी भी मामले पर नियम बनाने का अधिकार देती है। ऐसे नियमों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। यह संक्षेप में अधिनियम की योजना है।

अधिनियम की धारा 14(3) के तहत एक नामित न्यायालय को सत्र न्यायालय की शक्तियां प्रदान की जाती हैं और उसे अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की सुनवाई करने की आवश्यकता होती है जैसे कि वह एक सत्र न्यायालय हो। मुकदमे में जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए वह सत्र न्यायालय के समक्ष मामलों की सुनवाई के लिए संहिता में निर्धारित है। यह निश्चित रूप से अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन है जिसका अर्थ है कि यदि अधिनियम में कोई प्रावधान है जो ऐसे परीक्षणों के लिए संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है, तो यह अधिनियम की प्रक्रिया है जो प्रचलित होगी। सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे की प्रक्रिया संहिता के अध्याय XVIII में निर्धारित की गई है। धारा 225 लोक अभियोजक को अभियोजन के संचालन का प्रभारी बनाती है। धारा 226 के तहत उसे अभियुक्त के खिलाफ आरोप का वर्णन करके और यह बताते हुए अभियोजन मामले को खोलने की आवश्यकता है कि वह किस सबूत के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ अपराध साबित करने का प्रस्ताव करता है। एक बार ऐसा हो जाने पर न्यायाधीश विचार करेगा कि आरोप तय किया जाए या नहीं। संहिता की धारा 227 इस प्रकार है:

"यदि, मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने और इस संबंध में अभियुक्त और

अभियोजन पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद, न्यायाधीश मानता है कि अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया जाएगा और ऐसा करने के लिए उसके कारणों को दर्ज किया जाएगा।"

इस धारा के तहत न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर अपना दिमाग लगाए और यदि रिकॉर्ड की जांच करने पर उसे आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिलता है, तो उसे आरोपमुक्त कर देना चाहिए। दूसरी ओर, यदि इस तरह के विचार और सुनवाई के बाद वह संतुष्ट है कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो उसे संहिता की धारा 228 के अनुसार आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। एक बार आरोप तय हो जाने के बाद आम तौर पर मुकदमा आरोपी की दोषसिद्धि या बरी होने के साथ समाप्त होना चाहिए। यह संक्षेप में संहिता की धारा 225 से 235 की योजना है।

नई संहिता में पहली बार पेश की गई धारा 227, न्यायाधीश को किसी आरोपी को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की विशेष शक्ति प्रदान करती है यदि 'रिकॉर्ड और दस्तावेजों पर विचार करने पर वह मानता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है' आरोपी के खिलाफ दूसरे

शब्दों में, उस स्तर पर रिकॉर्ड और दस्तावेज़ पर उनका विचार यह सुनिश्चित करने के सीमित उद्देश्य के लिए है कि अभियुक्त के खिलाफ मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं। यदि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह धारा 228 के तहत आरोप तय करेगा, यदि नहीं तो वह आरोपी को आरोपमुक्त कर देगा। यह याद रखना चाहिए कि इस धारा को संहिता में उन मामलों पर सार्वजनिक समय की बर्बादी से बचने के लिए पेश किया गया था, जो प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा नहीं करते थे और अभियुक्तों को परिहार्य उत्पीड़न और व्यय से बचाते थे।

अगला सवाल यह है कि उस स्तर पर ट्रायल कोर्ट द्वारा 'विचार' का दायरा और दायरा क्या है। क्या वह मामले के रिकॉर्ड और अपने सामने रखे गए दस्तावेजों में पाए गए सबूतों को एकत्र कर सकता है जैसा कि वह आरोप तय होने के बाद अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों के निष्कर्ष पर करेगा? यह स्पष्ट है कि चूंकि वह यह तय करने के चरण में है कि आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं या नहीं, इसलिए उसकी जांच आवश्यक रूप से यह तय करने तक सीमित होनी चाहिए कि क्या रिकॉर्ड और दस्तावेजों से उभरने वाले तथ्य उस अपराध का गठन करते हैं जिसके लिए आरोपी दोषी है। आरोपी उस स्तर पर वह उस

सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्यों को छांट सकता है, लेकिन उसे अनाज को भूसी से अलग करने की दृष्टि से साक्ष्यों को एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है। उसे इस बात पर विचार करने के लिए कहा जाता है कि क्या आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार है और इस सीमित उद्देश्य के लिए उसे रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के साथ-साथ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर भी विचार करना चाहिए। बिहार राज्य बनाम रमेश सिंह, [1978] 1 एससीआर 257 में इस न्यायालय ने कहा कि आरोप तय करने के प्रारंभिक चरण में यदि कोई मजबूत संदेह-सबूत है जो न्यायालय को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि अनुमान लगाने का आधार है यदि अभियुक्त ने अपराध किया है तो न्यायालय को यह कहने का अधिकार नहीं है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। यदि अभियोजक अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए जो साक्ष्य पेश करने का प्रस्ताव करता है, भले ही उसे जिरह द्वारा चुनौती दिए जाने से पहले पूरी तरह से स्वीकार कर लिया गया हो या बचाव साक्ष्य द्वारा खंडन किया गया हो, यदि कोई हो, यह नहीं दिखा सकता कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो वहाँ मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगा। भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल एवं अन्य, [1979] 2 एससीआर 229 में, इस न्यायालय ने धारा 227 के

दायरे पर विचार करने के बाद पाया कि 'आरोपी के खिलाफ कार्यवाही के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं' शब्द स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि न्यायाधीश न केवल अभियोजन पक्ष के आदेश पर आरोप तय करने के लिए, बल्कि उसे यह निर्धारित करने के लिए मामले के तथ्यों पर अपने न्यायिक दिमाग का प्रयोग करना होगा कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के लिए मामला बनाया गया है। इस तथ्य का आकलन करने में अदालत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह मामले के पक्ष और विपक्ष में जाए या सबूतों और संभावनाओं को तौले और संतुलित करे, लेकिन वह यह पता लगाने के लिए सामग्री का मूल्यांकन कर सकता है कि क्या इससे उभरने वाले तथ्य उनके अंकित मूल्य पर लिए गए हैं। उक्त अपराध का गठन करने वाले तत्वों को स्थापित करें। इस विषय पर केस कानून पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला:

"(1) कि न्यायाधीश को संहिता की धारा 227 के तहत आरोप तय करने के सवाल पर विचार करते समय यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए सबूतों को छांटने और तौलने की निस्संदेह शक्ति है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं।

(2) जहां अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है, जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है, अदालत आरोप तय करने और मुकदमे को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से उचित होगी।

(3) प्रथम दृष्टया मामले को निर्धारित करने का परीक्षण स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नियम बनाना मुश्किल है। हालाँकि, बड़े पैमाने पर, यदि दो दृष्टिकोण समान रूप से संभव हैं और न्यायाधीश संतुष्ट है कि उसके सामने पेश किए गए साक्ष्य कुछ संदेह पैदा करते हैं, लेकिन आरोपी के खिलाफ गंभीर संदेह नहीं है, तो वह आरोपी को दोषमुक्त करने का पूरा अधिकार होगा।

(4) यह कि न्यायाधीश संहिता की धारा 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, जो वर्तमान संहिता के तहत एक वरिष्ठ और अनुभवी न्यायाधीश है, केवल एक डाकघर या अभियोजन पक्ष के मुखपत्र के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि उसे कार्य करना होगा -

मामले की व्यापक संभावनाओं, अदालत के समक्ष पेश किए गए सबूतों और दस्तावेजों के कुल प्रभाव, मामले में दिखाई देने वाली किसी भी बुनियादी कमजोरी आदि को ध्यान में रखें। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायाधीश को मामले के पक्ष और विपक्ष की गहन जाँच करनी चाहिए और सबूतों को ऐसे तौलना चाहिए जैसे कि वह कोई सुनवाई कर रहा हो।"

पुनः अधीक्षक में. और कानूनी मामलों के स्मरणकर्ता, पश्चिम बंगाल बनाम अनिल कुमार भुंजा और अन्य, [1979] 4 एससीसी 274 इस न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 18 में निम्नानुसार देखा:

"परीक्षण, सबूत और निर्णय का मानक, जिसे आरोपी को दोषी या अन्यथा घोषित करने से पहले अंतिम रूप से लागू किया जाना है, वास्तव में आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 227 या 228 के चरण में लागू नहीं किया जाना चाहिए। इस चरण में, यहां तक कि मजिस्ट्रेट के समक्ष सामग्री पर स्थापित एक बहुत मजबूत संदेह भी, जो उसे कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यात्मक तत्वों के अस्तित्व के बारे में एक अनुमानित राय बनाने के लिए

प्रेरित करता है, आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने को उचित ठहरा सकता है। उस अपराध का कमीशन"।

उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि धारा 227-228 के चरण में न्यायालय को रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वहां उभरने वाले तथ्य उनके अंकित मूल्य पर लिए गए हैं। कथित अपराध को बनाने वाले सभी घटकों के अस्तित्व का खुलासा करें। न्यायालय इस सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्यों की जांच कर सकता है क्योंकि उस प्रारंभिक चरण में भी यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि अभियोजन पक्ष द्वारा कही गई सभी बातों को ईश्वरीय सत्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, भले ही वह सामान्य ज्ञान या मामले की व्यापक संभावनाओं के विपरीत हो।

यह अधिनियम एक दंडात्मक क़ानून है। इसके प्रावधान इस मायने में कठोर हैं कि वे न्यूनतम दंड प्रदान करते हैं और कुछ मामलों में बड़ी हुई सजा भी प्रदान करते हैं; पुलिस अधीक्षक के स्तर से नीचे के पुलिस अधिकारी के सामने दिए गए इकबालिया बयानों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य बनाना और धारा 21 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से (डी) में बताए गए तथ्यों के सबूत पर खंडन योग्य अनुमान लगाना अनिवार्य है।

जिस आरोपी का पता नहीं चल पाता है उसकी पहचान तस्वीरों के माध्यम से करने के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। ये आतंकवाद के खतरे को नियंत्रित करने की दृष्टि से अधिनियम में पेश किए गए कुछ विशेष प्रावधान हैं। ये प्रावधान सामान्य कानून से अलग हैं क्योंकि उक्त कानून को अपराधियों के विशेष वर्ग से निपटने के लिए अपर्याप्त और पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं पाया गया। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ। इसलिए, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विधायिका ने ऐसे अपराधों को गंभीर प्रकृति का माना है जिन्हें सामान्य कानून के तहत रोका या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और इससे निपटने के लिए निवारक प्रावधान बनाए गए हैं। इसलिए, विधायिका ने विशेष प्रावधान बनाए, जिन्हें कुछ मामलों में कठोर कहा जा सकता है, ऐसे मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक विशेष मंच बनाया गया, अपराध की धारणा बनाने के लिए प्रावधान किया गया, रिहाई के संबंध में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए अपराधी को जमानत पर रिहा कर दिया, और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से प्रक्रिया में उपयुक्त परिवर्तन किए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि कानून के तहत किसी आपराधिक अपराध के लिए कारावास की सजा देने वाले कानूनों को सख्ती से समझा जाना चाहिए। उस्मानभाई

दाऊदभाई मेमन और अन्य बनाम गुजरात राज्य, [1988] 2 एससीसी 271

में इस न्यायालय ने फैसले के पैराग्राफ 15 में निम्नानुसार कहा:

"यह अधिनियम एक चरम उपाय है जिसका सहारा तब लिया जाता है जब पुलिस सामान्य दंड कानून के तहत स्थिति से नहीं निपट सकती। इसका इरादा देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवाद के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए विशेष मशीनरी प्रदान करना है। हालांकि, चूंकि, अधिनियम एक कठोर उपाय है, आमतौर पर इसका सहारा तब तक नहीं लिया जाना चाहिए जब तक कि सरकार की कानून लागू करने वाली मशीनरी विफल न हो जाए।"

इसे अलग ढंग से कहें तो निर्णय का अनुपात यह है कि यदि अभियुक्तों की गतिविधियों की प्रकृति को देश के सामान्य कानून के तहत जांचा और नियंत्रित किया जा सकता है तो अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल उन मामलों में है जहां कानून लागू करने वाली मशीनरी आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों के खतरे से निपटने के लिए सामान्य कानून को अपर्याप्त या पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं पाती है, तब अधिनियम के कठोर प्रावधानों का पालन करने वाले प्रावधान का सहारा लेना चाहिए। अधिनियम जैसे आपराधिक कानून

को लागू करते समय, अभियोजन पक्ष मामले के रिकॉर्ड और जांच के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेजों से यह दिखाने के लिए बाध्य है कि इससे उभरने वाले तथ्य प्रथम दृष्टया कानून के अक्षर के भीतर एक अपराध का गठन करते हैं। जब कोई कानून देश के सामान्य दंड कानूनों के तहत समान अपराधों के लिए निर्धारित दंड की तुलना में विशेष या बड़ी हुई सजा प्रदान करता है, तो न्यायाधीश पर एक उच्च जिम्मेदारी और कर्तव्य डाला जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लगाए गए आरोप का समर्थन करने के लिए प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा- जब कोई कानून गंभीर दंडात्मक भावना वाले किसी व्यक्ति का दौरा करता है- यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त देखभाल की जानी चाहिए कि जिन लोगों को कानून- प्रकृति की अभिव्यक्त भाषा द्वारा कवर किए जाने का इरादा नहीं था। कानून की भाषा को खींचकर कानून में शामिल नहीं किया जाता है। लेकिन उस का मतलब यह नहीं है कि न्यायिक अधिकारी ने निर्णय लेने के लिए बुलाया था या अधिनियम के तहत आरोप तय करने का मामला नहीं बनता है तो नकारात्मक रवैया अपनाना चाहिए। यदि अभियोजन पक्ष यह दर्शाता है कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री और जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, उससे यह संदेह होता है कि

आरोपी ने उसके खिलाफ कथित अपराध किया है, तो उसे आरोप तय करना चाहिए।

अब हम ऊपर बताए गए कानून को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अभियोजन पक्ष ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यह है कि उन्होंने एक गैरकानूनी सभा का गठन किया, राजू की हत्या कर दी और केशव को 'लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग' यानी इलाके के निवासियों में चाकू और लोहे की छड़ जैसे घातक हथियारों का उपयोग करके आतंकित करने के इरादे से घायल कर दिया। इस प्रकार दंड संहिता और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत अपराधों के साथ पठित अधिनियम की धारा 3(1) के तहत दंडनीय अपराध किए गए। जब घायल केशव ने 12 जुलाई, 1989 को शिकायत दर्ज कराई तो अधिनियम की धारा 3(1) के तहत कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अपराध पहली बार 29 जुलाई, 1989 को पेश किया गया था। इसका मतलब है कि 12 जुलाई, 1989 और 29 जुलाई, 1989 के बीच जांच अधिकारी ने साक्ष्य एकत्र किए जिससे उन्हें अपराध दर्ज करने में मदद मिली। अधिनियम की धारा 3(1) के तहत। जब 2 सितंबर, 1989 को पहली जमानत अर्जी का निपटारा किया गया, तो नामित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रथम दृष्टया अधिनियम की

धारा 3(1) लागू नहीं होती है। उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नामित न्यायालय ने गवाहों के बयानों की जांच की, जिन पर अभियोजन मामले का समर्थन करने के लिए भरोसा किया गया था कि अधिनियम की धारा 3(1) आकर्षित हुई थी। बता दें कि आरोपी संतोष राठौड़ साइकिल रिपेयरिंग की दुकान चलाता है। घटना के एक दिन पहले मृतक राजू साइकिल की दुकान पर गया था क्योंकि उसकी ट्यूब पंचर हो गई थी। उस समय आरोपी जितेंद्र और कुछ अन्य लोग साइकिल की दुकान पर मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में आरोपी जितेंद्र ने निम्नलिखित कहा है:

"वर्तमान में शहर में राजू और केशव का दबदबा है। उनकी जान लेकर हम शहर के दादा बन जाएंगे। तब इस शहर में हमारा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। राजू और केशव की हत्या के कारण आतंक से लोग डर जायेंगे।"

यह बात राजू नारायण, सुखाराम शिंदे और भाऊ साहब के बयानों से उजागर होती है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष के अनुसार अपराध की उत्पत्ति प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों को खत्म करके अंडरवर्ल्ड में वर्चस्व हासिल करना था। राम लोखंडे संबंधित घटना के बारे में बोलते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हमलावरों को यह कहते हुए सुना था कि राजू और केशव को खत्म करने पर वे दादा बन जाएंगे और उनके खिलाफ आवाज उठाने की

हिम्मत नहीं करेगा। भीका ने उसी दिन सुबह करीब 11.30 बजे पिछली घटना के बारे में बात की, जिससे पता चलता है कि दोनों गिरोहों के बीच प्रतिद्वंद्विता थी। श्री मासोदकर, राज्य सरकार के विद्वान वकील और साथ ही अपीलकर्ता इसलिए, आपराधिक अपील संख्या 703/89 में तर्क दिया गया कि हिंसा के कृत्य बड़े पैमाने पर लोगों और विशेष रूप से उस इलाके के निवासियों में आतंक पैदा करने के इरादे से किए गए थे जहां अपराध किया गया था। हमारा ध्यान गवाहों के कुछ बयानों पर भी गया कि कुछ आरोपी व्यक्ति शिव सेना पार्टी के सदस्यों से संबंधित थे। नामित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसके समक्ष रखी गई सामग्री और जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए बयान अधिनियम की धारा 3(1) के तहत किसी अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं। नामित न्यायालय के अनुसार आरोपी व्यक्तियों का इरादा लोगों या लोगों के एक वर्ग में आतंक पैदा करना नहीं था, बल्कि अंडर-वर्ल्ड में वर्चस्व हासिल करने की दृष्टि से केवल राजू और केशव को खत्म करना था। नामित न्यायालय की अध्यक्षता करने वाले विद्वान न्यायाधीश फिर निम्नलिखित कहा:-

"सच है कि कुछ लोग आतंक से त्रस्त हो सकते हैं और आतंक नग्न कृत्य का परिणाम हो सकता है, लेकिन लोगों में आतंक पैदा करना इस नग्न कृत्य का उद्देश्य नहीं

था। यदि लोग आतंक से त्रस्त हो रहे हैं तो, यह वे कुछ लोग हैं जो अपराध के आधार पर जीते हैं, न कि लोगों के आधार पर- कानून का पालन करने वाले अधिकांश नागरिक इन बयानों के अनुसार, इस अपराध में अंडरवर्ल्ड की सर्वोच्चता का दावा करने वाले दो युद्धरत गुटों के बीच झगड़े के अलावा और कुछ नहीं है।”

विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि सरकार की कानून लागू करने वाली मशीनरी विफल हो गई है और आतंकवाद के खतरे से निपटने की दृष्टि से अधिनियम के कठोर प्रावधानों का सहारा लेना आवश्यक हो गया है।

हमने गवाहों के बयानों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है जिन पर अभियोजन पक्ष अपने तर्क के समर्थन में निर्भर किया गया है कि आरोपी ने अधिनियम की धारा 3(1) के तहत अपराध किया था। हमारा मानना है कि नामित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि आरोपी व्यक्तियों का इरादा अंडरवर्ल्ड में वर्चस्व हासिल करने के लिए राजू और केशव को खत्म करना था। केवल इस आशय का बयान कि ऐसी हिंसा का प्रदर्शन लोगों के मन में आतंक या भय पैदा करेगा और कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करेगा, अधिनियम की धारा 3(1) के तहत

अपराध नहीं माना जा सकता। यह हिंसक कृत्य का परिणाम हो सकता है लेकिन इसे अपराध करने वालों का इरादा नहीं कहा जा सकता। पहले निकाले गए बयान से यह स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्तियों का इरादा प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करना और अंडरवर्ल्ड में वर्चस्व हासिल करना था ताकि वे इलाके के दबंगों के रूप में जाने जाएं और उनसे खूंखार हों। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उनका इरादा लोगों या लोगों के एक वर्ग में आतंक फैलाना था और इस तरह आतंकवादी कृत्य करना था। इससे साफ है कि एक तरफ आरोपी पक्ष और दूसरी तरफ राजू और केशव के बीच दुश्मनी थी। पूर्व वर्चस्व हासिल करना चाहता था जिसके लिए बाद वाले को समाप्त करना आवश्यक हो गया। इस दृष्टि से उन्होंने राजू और केशव पर हमला किया, पहले को मार डाला और दूसरे को घायल कर दिया। उनका इरादा स्पष्ट रूप से उन्हें खत्म करना था, न कि लोगों या लोगों के एक वर्ग में आतंक पैदा करना। यह अलग बात होती अगर आतंक फैलाने के लिए कुछ निर्दोष लोगों को मार दिया जाता। उस स्थिति में इरादा आतंक पर हमला करने का होगा और हत्याएं उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए होंगी। मौजूदा मामले में इरादा राजू और केशव को खत्म करना था और इस तरह अंडरवर्ल्ड में वर्चस्व हासिल करने का उद्देश्य हासिल करना था। ऐसी हिंसा के परिणाम से दहशत और भय पैदा होना

स्वाभाविक है, लेकिन अपराध करने का इरादा लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक पैदा करना नहीं कहा जा सकता है। इसलिए, हमारा विचार है कि नामित न्यायालय का यह मानना पूरी तरह से उचित था कि रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री और जिन दस्तावेजों पर भरोसा किया गया है, वे प्रथम दृष्टया अधिनियम की धारा 3(1) के तहत दंडनीय अपराध के घटित होने का खुलासा नहीं करते हैं।

महाराष्ट्र राज्य के विद्वान वकील द्वारा अगली दलील दी गई कि धारा 12(1) के तहत, अधिनियम के तहत अपराध की कोशिश करते समय, नामित न्यायालय किसी अन्य अपराध की कोशिश करने का हकदार था जिसके साथ आरोपियों पर उसी मुकदमे में आरोप लगाया गया था। दंड संहिता और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध एक ही घटना के दौरान किए गए थे। धारा 12(1) निस्संदेह नामित न्यायालय को अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के साथ-साथ किसी अन्य कानून के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई करने का अधिकार देती है, यदि पहला कानून दूसरे कानून से जुड़ा हो। हालाँकि, इसका मतलब यह नहीं है कि जब नामित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अधिनियम की धारा 3 (1) के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद नहीं है, तो उसे आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आगे

बढ़ना चाहिए। अन्य क़ानूनों के अंतर्गत अपराध यह अधिकार क्षेत्र को हड़पने के समान होगा। इसलिए, धारा 18 में प्रावधान है कि जहां किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद नामित न्यायालय की राय है कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है। इस बात के बावजूद कि उसके पास ऐसे अपराध की सुनवाई का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।

अलग होने से पहले हम बता सकते हैं कि अभियुक्तों के विद्वान अधिवक्ता वकील श्री ललित ने हमारे सामने यह आग्रह करने की कोशिश की है कि अधिनियम के प्रावधानों का उद्देश्य राज्य की सुरक्षा को कमजोर करने वाले राजनीतिक आतंकवाद से निपटना है, न कि सामान्य क़ानून और व्यवस्था के लिए समस्या खड़ी करना। हम इस बड़े सवाल पर जाना जरूरी नहीं समझते क्योंकि, हमारी राय में, नामित न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही था कि यह अंतर-गिरोह प्रतिद्वंद्विता का मामला था, जो अधिनियम की धारा 3(1) के तहत नहीं आता।

उपरोक्त दृष्टिकोण से हम मानते हैं कि तीनों अपीलें विफल हैं और खारिज की जाती हैं। अभियुक्त के विद्वान वकील श्री ललित ने कहा कि चूंकि उच्च न्यायालय ने मामले के शीघ्र निपटान का निर्देश दिया है, इसलिए वह जमानत से इनकार करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ निर्देशित विशेष अनुमित याचिका पर दबाव नहीं डालेंगे। उक्त

कथन के मद्देनजर, विशेष अवकाश याचिका संख्या 2459/89 को दबाए नहीं जाने के कारण निस्तारित कर दिया जाएगा। यह निर्देशित किया जाता है कि जिस सत्र न्यायालय में मामला स्थानांतरित किया जाता है, व न्यायालय यथाशीघ्र परीक्षण पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अधिमानतः इस न्यायालय के हस्तगत आदेश कि प्राप्ति की तारीख से चार महीने के भीतर।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अश्लेषा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।